

इस अस्थिर कांग्रेस सरकार के प्राण कब निकल जाएं पता नहीं: सतीश पूनिया

भाजपा द्वारा राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारी के सिलसिले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया डूंगरपुर पहुंचे

डूंगरपुर/जयपुर, 28 नवम्बर (का.सं.) भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने डूंगरपुर पार्टी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य, भ्रष्ट और अराजक सरकार नहीं देखी, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी। 2018 में कांग्रेस का जो विघटन शुरू हुआ, जब राजभवन में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी दो-दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, उसके बाद लगातार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर झगड़ा, सचिवालय में किसको कौन सा कमरा मिले, इसका झगड़ा, गाड़ी किसको कैसे मिले इसका झगड़ा और अतः परिणति यह हुई कि करीना का देश झेल रही जनता के साथ यह सरकार या तो भेदभाव कर रही थी या लापरवाही कर रही थी। अब हालत यह है कि इस अस्थिर कांग्रेस सरकार के प्राण कब निकल जाएं, पता नहीं।

भाजपा को भी कांग्रेस की सरकार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाने वाली जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेगेश्वर धाम के पवित्र प्रांगण में आयोजित श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतियोगिता महोत्सव एवं महायज्ञ में सम्मिलित होकर अनुष्ठान में

■ बेगेश्वर धाम में डॉ. पूनिया ने महायज्ञ में आहुति दी और कहा, 2018 में कांग्रेस का विघटन शुरू हुआ, राजभवन में दो-दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर झगड़ा हुआ।

■ राहुल गांधी राजस्थान यात्रा पर आ रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि, आपने कहा था, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 10 तक गिनती गिनेंगे और किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन 1700 दिन हो गए, कर्जा माफ नहीं किया।

आहुति दी। पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि 2018 में अलवर के थानागाड़ी गैंगरेप की गूंज पूरे देश में हुई, अलवर की निर्भया गैंगरेप की गूंज हुई और कोई दिन ऐसा नहीं होता जब अखबार रोजे नहीं होते दुष्कर्म, गैंगरेप हत्या, लूट इत्यादि घटनाओं से। क्या दृश्य होगा जब कोई नवजात के शव को श्वान नौचता हो, जो भी सरकारी अस्पताल में। जो क्या बिड़बना रही होगी जब भूख से बिचलखती कोई अबला रोटी मांगती है, एम्बुलेंसकर्मी से और वहीं एम्बुलेंस कर्मी उस महिला से दुष्कर्म करते हैं। क्या परिस्थिति रही होगी जहां मुख्यमंत्री विराजते हैं उससे कुछ दूर धर्मान्तरण हो रहा हो। क्या तकलीफ रही होगी जब किसी साधु या पुजारी को

या तो जलने पर मजबूर होना पड़ा या उसको जला दिया, यह राजस्थान की कानून व्यवस्था की बानगी है, राजस्थान ऐसा लगता है कि अपराधों की राजधानी हो गया है। उन्होंने कहा, दूसरा बड़ा मसला है कि राहुल गांधी यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने यह कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 10 तक गिनती गिनेंगे और राजस्थान के सारे किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। चार वर्ष हो गए, दिन तो 10 कहे थे, लेकिन 10 से भी कहीं ज्यादा 1700 दिन हो गए, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अब राजस्थान की धरती पर कदम रखें तो उस वादे को याद करें।



जनाक्रोश रैली की तैयारियों का जायजा लेने डूंगरपुर गए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने बेगेश्वर धाम में श्री हरिमंदिर स्वर्ण शिखर प्रतियोगिता महोत्सव में भाग लिया व महायज्ञ में भी शामिल हुए।

तीसरा बड़ा मसला रोजगार का है। उन्हीं के जन घोषणा पत्र में रोजगार की बात बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी। पर 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है राजस्थान में, लेकिन नतीजा क्या हुआ रीट, जेईएन, फार्मासिस्ट, लाइसेंसियर की जितनी नौकरियां थी उसमें नौकरी का आंकड़ा तो बताया सदन में एक लाख, परीक्षा दी 70 लाख ने, 69 लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में कोई रोडमैप सरकार के पास नहीं है।

उसमें कोढ़ में खाज का काम यह हुआ कि नकल जैसे एक संगठित अपराध ने राजस्थान के नौजवानों के भविष्य को उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया।

उन्होंने कहा कि एंटीइनकबेंसी, जिसे जनता का सरकार विरोधी रूझान कहते हैं, भी एक मुद्दा है। लेकिन मैं इसको खाली सत्ता विरोधी रूझान ही नहीं बोलता हूँ, इसको जनआक्रोश बोलता हूँ और इसलिए यह जो जन

आक्रोश अभियान है, यह जनता की उन्हीं चीजों को मुखर करने के लिए किया है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 15 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, हम लोग 2 करोड़ लोगों से जनसंपर्क करेंगे, दो सौ विधानसभा क्षेत्रों में 75 हजार किलोमीटर 200 तक रथ चलेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जनता से जनसंपर्क करेंगे। सभी विधानसभाओं में प्रभारी एवं सह-प्रभारी तैनात कर दिए गए हैं, जो मंडल और बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा तय करेंगे। इस माध्यम से 5 लाख कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण सक्रिय भागीदारी होने वाली है।

जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में 20 हजार चौपाल सभाएं एवं 20 हजार नुकड़ें सभाएं तय की गई हैं।

एक दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा का आरंभ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नट्टारथों की रवानगी से जयपुर से करेंगे, पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक 200 रथ जाएंगे। 2 दिसंबर को जिलों से, 3 और 4 को विधानसभाओं से जन आक्रोश रथ यात्रा शुरू होंगी और लगातार 14 दिसंबर तक हर घर तक, हर दरवाजे तक कार्यकर्ता जाएंगे, और इस जन विरोधी कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे।

‘क्या आप गहलोत...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) क्योंकि यह स्पष्ट हो गया है कि, राहुल गांधी का तो चुनाव ना ही राजनीति और उसके परिणाम पर फोकस करने में कोई रुचि है।

ए.आई.सी.सी. के वरिष्ठ पदाधिकारी यात्रा में व्यस्त हैं तथा ए.आई.सी.सी. का संचालन रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर कमलनाथ, दिग्विजयसिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता विद्यमान थे।

रोचक बात यह है कि, राहुल गांधी जो कहते हैं और असलियत में जो हो

रहा है उसमें उन्हें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में पूछे गए इस प्रश्न पर, कि क्या लोटने पर पार्टी में उनका स्वागत होगा, राहुल गांधी ने कहा, जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं यदि उन्हें रिश्तत दी गई है तो उनका लोटना मुश्किल होगा।

राहुल गांधी मूलतः यात्रा के बारे में अपना सोच आगे बढ़ाने पर फोकस कर रहे थे और कि, यात्रा में उनको इतनी दिलचस्पी क्यों है। लेकिन वरिष्ठ नेताओं का कहना है, संगठन की उपेक्षा का नतीजा पार्टी को चुकाना पड़ रहा है, चुनावी राजनीति के संदर्भ में।

जबरन धर्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल नहीं है। केन्द्र का यह जवाब उस याचिका पर आया है, जो कपटपूर्ण धर्म-परिवर्तन तथा डराने-धमकाने तथा उपहारों एवं मौखिक लाभों के जरिये छलपूर्वक प्रलोभन देकर धर्म-परिवर्तन करने के खिलाफ दायर की गई है। केन्द्र ने कहा कि इसका धर्म-परिवर्तन अनुच्छेद 14, 21 तथा 25 का उल्लंघन करता है। केन्द्र ने एक शपथ-पत्र पेश किया, जिसमें जबरन धर्म-परिवर्तन के खिलाफ गंभीर कदम उठाए जाने का संकल्प लिया है। केन्द्र ने कहा कि जबरन धर्म-परिवर्तन के खिलाफ कानून लाना आवश्यक है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को इससे बचाया जा सके। केन्द्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जहाँ छल-कपट, धोखाधड़ी, बल प्रयोग, प्रलोभन या अन्य ऐसे ही तरीकों से देश के कमजोर वर्गों का धर्मान्तरण संगठित, नियोजित तथा परिष्कृत तरीके से किया गया है। केन्द्र ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने

कहा कि “प्रचार” शब्द में किसी व्यक्ति के धर्म के परिवर्तन का अधिकार निहित नहीं है, इस शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अपने सिद्धांतों का निरूपण करके अपने धर्म का प्रसार करना।

केन्द्र ने कहा कि वह इस याचिका में उठाये गये मुद्दे की गंभीरता से परिचित है, तथा समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें महिलायें तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल हैं, के अधिकारों के संरक्षण के लिये कानून बनाना जरूरी है। नौ राज्य इस विषय पर पहले ही कानून बना चुके हैं। ये राज्य हैं- ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तथा हरियाणा।

14 नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जबरन धर्मान्तरण “बहुत गंभीर मुद्दा” है तथा इससे देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अदालत ने केन्द्र से कहा कि इस बावत अपना रुख स्पष्ट करे कि जबरन धर्मान्तरण को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

‘एक अच्छे ‘गॉल्फर’ की भांति...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एल्बर्टा तीसरे नम्बर का सबसे अच्छा शॉट होता है बर्डी, जो कि दुर्लभ होता है। उससे बेहतर है बड़ा “बर्ड” इंगल जो और भी ज्यादा दुर्लभ है और उससे भी बेहतर है एल्बर्टा।

मैं कहूँगा कि उन्होंने शुरूआत कई प्रकार के “बर्डी” शॉट्स से की। वे ना केवल महलों से निकल कर सड़कों पर उतरे बल्कि आम लोग, निर्धन से भी प्रतिस्पर्धी वे भी थोड़ा मिल गए। निश्चित रूप से अमीर लोग भी उनके साथ आए जैसे रिया सेन, अमोल पालेकार।

हिन्दुस्तान टाइम्स की एंटरटेनमेंट डैस्क ने खबर दी थी कि रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी भी शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चलीं तोनों की तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके अलावा महाराष्ट्र में रिया सेना से पहले पूजा भट्ट और रिशे देशमुख भी यात्रा में शामिल हुए। अब नैशनल मीडिया भी इस नए गॉल्फर को देख रहा है और फरिन मीडिया जो उनकी वाक को नेहरूवादी जुमला करार देकर खारिज कर रहा था वह भी अपनी टी.वी.

टीम भेज रहा है यात्रा कवरेज करने के लिए जैसे बी.बी.सी।

बी.बी.सी. रिपोर्टर ने कहा “भाजपा ने राहुल की यात्रा को ऐसा मिशन कह कर खारिज कर दिया जिसमें ऐसे देश को जोड़ने की बात कह रहे हैं जो कभी भी टूटा नहीं था लेकिन गत 75 दिनों से कई बॉलीवुड एक्टर, कई शिक्षाविद्, एक्टिविस्ट यहां तक विश्वेश नेता, जो कांग्रेस के घोर विरोधी थे, वे भी गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं।” उक्त रिपोर्टर ने गांधी के साथ हजारों किलोमीटर का सफर कर रहे लोगों से बात की। “हेदराबाद के एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, ने बताया कि वह यहां इसलिए है क्योंकि मौजूदा सरकार से उसका मोहभंग हो गया है। दम्पती जो पुणे में आइसक्रिम पॉपल चलाया था, ने विरोध का बैनर उठाया है। उनका दावा है कि यह भारत के विश्वविद्यालयों का राजनैतिक करण है। कई ग्रामीणों ने कहा वे तो सिर्फ उत्सुक हैं और देखने आए हैं। क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां कभी इतना बड़ा

कोई कार्यक्रम नहीं हुआ।” मध्य प्रदेश में उनके भाषण में आदिवासियों की भारी भीड़ ने देखा कि, “भले मानुस” राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जातिवादी, स्वर्णवादी, आदिवासी विरोधी नीतियों का पर्दाफाश कर दिया कि प्रसार मोदी आदिवासियों को वनवासी के रूप में परिभाषित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा “आप आदिवासी हैं।” “इस पर ना तो ना तो ऊंगली उठाई गई ना मुझे लहवाई गईं और ना ही मोदी के बाप-दादा का नाम लिया गया।

राहुल ने कहा, आप आदिवासी हैं इसका आप मतलब है इसका मतलब है कि आप भारत के मूलभूत निवासी हैं। इसका अर्थ है कि जब भारत में कोई नहीं रहता था आप तब भी यहां थे। इसलिए आप इस देश के पहले नागरिक हैं इसलिए आपके साथ बेहतर निवास व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आपको इससे बर्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, मैंने देखा है नरेंद्र मोदी आपके लिए “वनवासी” शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि आप समाज के अंग नहीं हैं आप जंगल में रहते हैं।

लेकिन सरकार ने जंगल के अधिकार, जमीन, पेड़ सब निजी सैक्टर को बेच दिया है। तो जब जंगल नहीं होंगे आप भी समाज के अंग नहीं होंगे, आप जंगल का हिस्सा भी नहीं रह जायेंगे क्योंकि जंगल होंगे ही नहीं।” उन्होंने थोड़ी देर ही बोला इस समय वे अकेले थे उनके पीछे बाला-बात पर “तालियां” चिल्लाने वाला कोई “यस मेन” भी नहीं था। वीडियो में मैंने राहुल गांधी जिंदाबाद या हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, का नारा नहीं सुना।

राहुल ने किसी भी तरह की तारीफ या समर्थन नहीं मांगा, वे चाहते थे कि उनकी बात लोगों तक पहुंचे, अंत में उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है मैंने जो कहा आप समझ गए होंगे? ओह हाँ आपके चेहरे से लगता है कि आप समझ गए हैं। जयहिंद।”

साफ कहूँ तो मैंने देखा भी किसी नेता को ऐसा करने नहीं देखा यदि तक कि इंदिरा गांधी को भी नहीं, जबकि वो भीड़ खींचना जानती थीं। खेलते रहो राहुल, अच्छा गॉल्फ चल रहा है और मैं आपके लाखां प्रशंसकों में से एक हूँ।”

टॉक, 28 नवम्बर (निस)। बनास नदी क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्रों में बजरी लीज धारक द्वारा खनन करने से आक्रोशित ग्राम वजरीपुरा, लहन, बोराद, अहमदपुरा, नया गांव, पालडा के आक्रोशित किसानों व ग्रामीणों ने बजरी खनन स्थल पर पहुंच कर जमकर हंगामा किया और बजरी खनन करने वाले वाहनों में तोड़फोड़ भी कर दी।

इससे ग्रामीण व बजरी लीज धारक के कर्मी आमने-सामने हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लीजधारक की मारिईंग विभाग, प्रशासन व पुलिस विभाग से मिलीभगत है और वह अवैध रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र में बजरी खनन कर रहा है और बनास में बजरी खनन से उनके जलस्रोत सूखते जा रहे हैं और बेतरतीब खनन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो

आरोप है कि, बजरी लीज धारक बनास में अवैध रूप से बजरी खनन कर रहे हैं, जिससे जलस्रोत सूखते जा रहे हैं।

■ गुप्साए ग्रामीणों व किसानों ने ना केवल बजरी खनन रूकवा दिया बल्कि खनन कर रहे वाहनों में तोड़-फोड़ भी की।

आक्रोशित ग्रामीण खनन स्थल पर पहुंच गए और उनके आक्रोश के चलते खनन कार्य को रोकना पड़ा। मामले की जानकारी लगेते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध खनन फिर से करते हैं तो ग्रामीण प्रे नदी में उतरेगे।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिर से बजरी खनन चालू हुई है। ग्रामीणों व किसानों का बजरी लीज धारक नियम कायदे

कानूनों की ध्वजियां उड़ाकर खनन कर रहा है। ग्राम वजरीपुरा, लहन, बोराद, अहमदपुरा नया गांव, पालडा के किसान व ग्रामीण नदी में उतर गए और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ ने ना केवल बजरी खनन रूकवा दिया बल्कि खनन कर रहे वाहनों में तोड़फोड़ भी की। इससे वजरीपुरा के बनास नदी इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए घटना की जानकारी मिलते ही बजरी लीजधारक के अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित

ग्रामीणों से वार्ता की। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ शांत हुई। भीड़ में शामिल किसान आदिवासी का आरोप है कि बजरी लीज धारक के लोग नदी में चेकपोस्ट लगा अहमदपुरा की रवरा रसीद के नाम पर वजरीपुरा और मोलाईपुरा जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुलिस, प्रशासन और खनिज विभाग की मिलीभगत से बनास में बजरी निकालने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नियम कायदे कानूनों को ताक में रखकर किए जा रहे अवैध बजरी खनन से उनके क्षेत्रों के पानी के कुँए और अन्य जल स्रोत पूरी तरह से सूखने के कगार पर आ गए हैं, जिससे कृषि कार्यों में भी मुश्किल होने लगी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लीजधारक को चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन किया गया तो फिर से ग्रामीण नदी में उतरेंगे।

राष्ट्रपति शी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर काम करता है। इण्डो पैसफिक क्षेत्र में चीन के आर्थिक संबंध कुल मिलाकर चीन केन्द्रित रहे हैं। जिसमें उसका अधिकांश कारोबार चीन के साथ हुआ है। यदि कैनेडा के शेष एशियाई देशों के साथ किंग एग व्यापार को भी जोड़ लिया जाए, तो वह भी चीन के साथ हुए व्यापार की मात्रा से कम पड़ जाता है। कैनेडा अब चीन के अलावा एशिया के शेष देशों के साथ व्यापक व्यापार चाहता है और उसने इन देशों के लिए 750 मिलियन डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है। वह जी-7 देशों के उस वृद्धि किए गए 600 बिलियन डॉलर के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा होगा जो उन्होंने चीन के दबदबे का मुकाबला करने को लेकर एशिया के शेष देशों के लिए बनाया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस पहल को चीन के बैल्ट एण्ड रोड (बी.आर.आई.) प्रोग्राम का विकल्प माना जा रहा है। शी जिनपिंग के बी.आर.आई. के तहत लाए गए भारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राप्त करने वाले कई देश कर्जे के जाल में फंस चुके हैं। परिणामस्वरूप इन प्रोजेक्ट्स के प्राप्तकर्ता देश विपरीत प्रतिक्रियाएं देने को बाध्य हैं।

चीन के द्वारा बी.आर.आई. के तहत विशाल प्रोजेक्ट्स लाए गए थे जो आर्थिक रूप से टिकाऊ साबित नहीं हुए। परिणामस्वरूप जिन देशों ने ऋण लेकर इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, अब वे ऋण उनके गले की फांस बन चुके हैं। ये प्रोजेक्ट्स अन्य देशों के अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक बढहाली ला चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति अभिमाना रूख और चीन का उभरता दबदबा बड़े देशों के साथ उसके संबंधों को खतरे में डाल रहा है। यद्यपि छोटे देशों के लिये चीन एक दुर्घर्ष शक्ति हो सकता है, लेकिन कौ धारणाएं बड़े देशों को उससे घृणा करने के अवसर प्रदान कर रही है। अतः वैकल्पिक गठबंधन बन रहे हैं जिनका परिणाम अन्ततः चीन के साथ अधिक विवादामय रूख के रूप में हो सकता है। चीन की संप्रभुता की धारणाओं के कारण एक नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही है।

अल्पसंख्यक छात्र को आतंकवादी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से यह क्रॉस क्वेश्चन किया कि वह उसे आतंकवादी कैसे कह सकते हैं। वायरल हुए एक वीडियो क्लिप में छात्र को प्रोफेसर को यह प्रश्न करने सुना जा सकता है। उन्होंने बिना किसी प्रूफ के उसे आतंकवादी क्यों कहा। प्रोफेसर इस प्रश्न का उन्होंने सिर्फ कुछ अपूर्ण उदाहरण दिए जो छात्र के गले नहीं उतरे। इस पूरी घटना से हर कोई बेखबर रहता लेकिन सोशल मीडिया की वजह से यह प्रकाश में आ सकी। एक बार ट्वीट किए जाने के बाद पोस्ट वायरल हो गई। इसके बाद बैंगलोर के मनिपाल इन्स्टीट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी ने प्रोफेसर को निलम्बित

महाराष्ट्र के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दट्ठीट किया कि “संस्थान इस घटना को लेकर पहले ही जांच शुरू कर चुका है और जांच पूर्ण होने तक संबंधित शिक्षक को पढ़ाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम सबको यह बताना चाहते हैं कि संसदीय इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस एक मात्र घटना को संस्थान की नीति के अनुरूप संभाला जाएगा।

ट्वीट में आगे कहा गया है कि “संस्थान को इस बात का गर्व है कि उसके कैम्पस में एक सर्वाधिक योग्य छात्र संगठन है और वह जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग से परे सबके साथ समान व्यवहार कर होंगे।” एम.आई.टी. बैंगलोर ने भी

दट्ठीट किया कि “संस्थान इस घटना को लेकर पहले ही जांच शुरू कर चुका है और जांच पूर्ण होने तक संबंधित शिक्षक को पढ़ाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम सबको यह बताना चाहते हैं कि संसदीय इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस एक मात्र घटना को संस्थान की नीति के अनुरूप संभाला जाएगा।

ट्वीट में आगे कहा गया है कि “संस्थान को इस बात का गर्व है कि उसके कैम्पस में एक सर्वाधिक योग्य छात्र संगठन है और वह जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग से परे सबके साथ समान व्यवहार कर होंगे।” एम.आई.टी. बैंगलोर ने भी

दट्ठीट किया कि “संस्थान इस घटना को लेकर पहले ही जांच शुरू कर चुका है और जांच पूर्ण होने तक संबंधित शिक्षक को पढ़ाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम सबको यह बताना चाहते हैं कि संसदीय इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस एक मात्र घटना को संस्थान की नीति के अनुरूप संभाला जाएगा।

ट्वीट में आगे कहा गया है कि “संस्थान को इस बात का गर्व है कि उसके कैम्पस में एक सर्वाधिक योग्य छात्र संगठन है और वह जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग से परे सबके साथ समान व्यवहार कर होंगे।” एम.आई.टी. बैंगलोर ने भी

समलैंगिक को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुसार किरपाल के नाम को “पुनर्विचार” के लिए सुप्रीम कोर्ट को लीजियम को भेजा गया है। तथापि, मैगोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर के प्रावधानों के तहत यदि केन्द्र सरकार को कोलीजियम द्वारा नाम पुनः भेजा जाता है तो सरकार को उसे मंजूरी नहीं पड़ेगी। किरपाल, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) बी.एन. किरपाल के पुत्र हैं। इण्डिया अहेड के अनुसार उनको अस्वीकार किए जाने का एक कारण यह प्रतीत होता है कि इस 50 वर्षीय एडवोकेट के पॉर्टर एक विदेशी है। उसने आगे जोड़ा कि इन्स्टीजेंस ब्यूरो के अनुसार उनके पॉर्टर सिक्वोरिटी के लिए एक रिस्क हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कोलीजियम द्वारा किरपाल के नाम को अक्टूबर 2017 में पहली बार मंजूरी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लेकर चर्चा में तीन बार विलम्ब कर चुका है। मार्च 2021 में सी.जे.आई. एस.ए. बोबडे ने विधि मंत्री रवि शंकर दास (शिवाजी के गुरु) के बिना, कोई भी व्यक्ति शिवाजी को नहीं जान पाता। भाजपा के कुछ वर्गों में यह धारणा बनती जा रही है कि कोशियरी के पद पर बने रहने से विपक्षी नेताओं को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुंचाने का मौका एवं आधार मिल जायेगा। तथा इन चुनावों के बाद 2024 में अति महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं।

समलैंगिक को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुसार किरपाल के नाम को “पुनर्विचार” के लिए सुप्रीम कोर्ट को लीजियम को भेजा गया है। तथापि, मैगोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर के प्रावधानों के तहत यदि केन्द्र सरकार को कोलीजियम द्वारा नाम पुनः भेजा जाता है तो सरकार को उसे मंजूरी नहीं पड़ेगी। किरपाल, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) बी.एन. किरपाल के पुत्र हैं। इण्डिया अहेड के अनुसार उनको अस्वीकार किए जाने का एक कारण यह प्रतीत होता है कि इस 50 वर्षीय एडवोकेट के पॉर्टर एक विदेशी है। उसने आगे जोड़ा कि इन्स्टीजेंस ब्यूरो के अनुसार उनके पॉर्टर सिक्वोरिटी के लिए एक रिस्क हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट कोलीजियम द्वारा किरपाल के नाम को अक्टूबर 2017 में पहली बार मंजूरी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लेकर चर्चा में तीन बार विलम्ब कर चुका है। मार्च 2021 में सी.जे.आई. एस.ए. बोबडे ने विधि मंत्री रवि शंकर दास (शिवाजी के गुरु) के बिना, कोई भी व्यक्ति शिवाजी को नहीं जान पाता। भाजपा के कुछ वर्गों में यह धारणा बनती जा रही है कि कोशियरी के पद पर बने रहने से विपक्षी नेताओं को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को नुकसान पहुंचाने का मौका एवं आधार मिल जायेगा। तथा इन चुनावों के बाद 2024 में अति महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं।

चीन में लॉकडाउन के विरोध में जनता सड़कों पर उतरी

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीजिंग, 28 नवंबर चीन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए देश की साम्यवादी सरकार द्वारा अपनायी गयी सख्त नीति के खिलाफ राजधानी बीजिंग सहित देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए हैं। जनता लॉकडाउन और आने-जाने के प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रही है और साथ ही चीन की साम्यवादी पार्टी के शासन का भी विरोध शुरू हो गया है। लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। चीन में चल रहे प्रदर्शन बीजिंग से शुरू होकर त्जैजि, लॉन्घो, शियान, चोंगकिंग, नूचन, झेंगझोऊ, आदि शहरों तक फैल चुके हैं।

‘जजों की नियुक्ति का कोलीजियम सिस्टम 1991 में शुरू हुआ’

विधि मंत्री रिजिजू के अनुसार, इससे पहले सरकार ही जजों की नियुक्ति करती थी, अतः कोलीजियम सिस्टम संविधान की देन नहीं है, जजों के निर्णय की देन है

—डॉ. सतीश मिश्रा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 28 नवम्बर। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच चल रही तनावनी आज उस समय उभरकर फिर सामने आ गई, जब सर्वोच्च न्यायालय ने जजों की नियुक्ति की कोलीजियम-व्यवस्था पर केन्द्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तथा कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिये था। न्यायालय ने केन्द्र द्वारा उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों में विलम्ब किये जाने के मुद्दे की ओर भी संकेत किया।

जजों की नियुक्ति की इस व्यवस्था पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अंधाधुंध प्रहारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “जब किसी उच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा कहता हैऐसा नहीं होना चाहिये था।” रिजिजू,

सुप्रीम कोर्ट विधि मंत्री की इस टिप्पणी से काफी विचलित हुआ तथा एडवोकेट जनरल व सॉलिसिटर जनरल को चेतावनी दी कि, अगर जजों की नियुक्ति का मामला अकारण लटकता रहा तो, सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन इस मुद्दे पर निर्णय पारित करना पड़ेगा।

जो इस बात को लेकर अपने अंसतोष को मुश्किल से ही छुपा पाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार की कुछ खास नहीं चलती है, ने हाल ही में वर्तमान नियुक्ति-तंत्र पर ताजातरीन हमला बोला तथा कहा कि कोलीजियम व्यवस्था संविधान के “प्रतिकूल” (एलिअन) है।

रिजिजू ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विवेक से ही, अदालत के एक फैसले के जरिये, कोलीजियम का सृजन किया था। उन्होंने कहा कि 1991 से पहले, सारे जजों की

नियुक्ति सरकार ही किया करती थी। टाइम्स नाउ समिट में बोलते हुए, कानून मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हर व्यक्ति के लिये, विशेष रूप से सरकार के लिये, एक “पवित्र दस्तावेज” है।

उन्होंने पूछा कि, “आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि केवल अदालतों या कुछ जजों द्वारा लिये ऐसे निर्णय, जो संविधान के प्रतिकूल हों, का समर्थन देश कैसे करेगा।” केन्द्र की ओर प्रस्तुत सॉलिसिटर जनरल के इस कथन कि “कभी-कभी मीडिया की रिपोर्ट गलत भी होती है” को विशेष तवज्जो

देते हुये, अदालत ने कहा: “मि. अटॉर्नी जनरल, मैंने सारी प्रेस-रिपोर्टों की अनदेखी कर दी है, लेकिन यह कथन एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से एक इन्टरव्यू के दौरान आया है, जो अभी उच्च पद पर आसीन है।मैं और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अगर हमें कुछ कहना पड़ा तो हम उसे निर्णय (के रूप में) कहेंगे।”

जस्टिस कौल ने केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी को जवाब देते हुए कहा। नियुक्तियों में विलम्ब के बिन्दु पर अदालत ने पूछा कि नैशनल जुडिशियल ऑफ ऑर्गनाइजेशन कमीशन (एन.जे.ए.सी.) अपनी कमीटी पर खर नहीं उतरा है क्या यही कारण है, जिससे सरकार प्रसन्न नहीं है, तथा इसीलिये नामों पर स्वीकृति नहीं दे रही है। कोलीजियम की सिफारिशों पर सरकार ने कुंडली मार के बैठने पर सर्वोच्च न्यायालय ने

कहा कि केन्द्र, अपनी आपत्तियां